



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 506]

नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 19, 2008/भाद्र 28, 1930

No. 506]

NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 19, 2008/BHADRA 28, 1930

विदेश मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 सितम्बर, 2008

भारत गणराज्य और मॉरीशस गणराज्य के बीच प्रत्यर्पण
संधि

सा.का.नि. 661(अ).—भारत गणराज्य तथा मॉरीशस गणराज्य के बीच प्रत्यर्पण संधि पर 21 नवम्बर, 2003 को नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए गए थे; तथा संधि के अनुसमर्थन संबंधी दस्तावेजों का आदान-प्रदान 23 जून, 2008 को पोर्ट लुईस में हुआ था तथा अनुच्छेद 20 के अनुसार अनुसमर्थन संबंधी दस्तावेजों के आदान-प्रदान की तारीख से यह संधि लागू हो गई है, तथा इस संधि के प्रावधान निम्नानुसार हैं :

भारत गणराज्य की सरकार और मॉरीशस गणराज्य की सरकार;

अपराधियों के पारस्परिक प्रत्यर्पण के लिए अन्य प्रावधान बनाकर अपराधों के दमन में दोनों देशों के बीच सहयोग को, और प्रभुत्व बनाने की इच्छा से;

यह स्वीकार करते हुए कि आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए ठोस उपाय करने आवश्यक हैं;

निम्नलिखित पर सहमत हुए हैं :

अनुच्छेद-एक

प्रत्यर्पण कर्तव्य

(1) प्रत्यर्पण संधिदाकारी राज्य इस संधि में विनिर्दिष्ट परिस्थितियों और शर्तों के अंतर्गत किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो अनुच्छेद दो में दिये अनुसार किसी प्रत्यर्पण अपराध को एक राज्य के क्षेत्र के भीतर

करने का आरोप है अथवा दोषसिद्ध है, और वह दूसरे राज्य के क्षेत्र के भीतर पाया जाता है, दूसरे संधिदाकारी राज्य को प्रत्यर्पित करने का वचन देता है चाहे यह अपराध इस संधि के लागू होने के पूर्व अथवा बाद में किया गया हो।

(2) अनुच्छेद दो में दिये अनुसार प्रत्यर्पण ऐसे अपराध के संबंध में भी किया जाएगा जो अनुरोधकर्ता राज्य के क्षेत्र से बाहर किया गया हो परन्तु उन पर उसका क्षेत्राधिकार है, बशर्तें सदृश परिस्थितियों में अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य का ऐसे अपराध पर न्यायाधिकार होता। ऐसी परिस्थितियों में अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य अपराध की गंभीरता सहित मामले की सभी परिस्थितियों को स्वीकार करेगा।

(3) इसके अतिरिक्त जैसा कि अनुच्छेद दो में उल्लेख किया गया है, किसी प्रत्यर्पणीय अपराध के लिए प्रत्यर्पण उपलब्ध होगा।

(क) यदि अपराध अनुरोधकर्ता राज्य के किसी राष्ट्रिक द्वारा किसी तीसरे राज्य में किया गया है और अनुरोधकर्ता राज्य अपराधी की राष्ट्रीयता को अपने न्यायाधिकार का आधार बनाता है; और

(ख) यदि अपराध अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य में होता है तो यह उस राज्य के कानूनों के अंतर्गत एक अपराध होगा जिसके लिए कम से कम एक वर्ष की कैद का दण्ड दिया जा सकता है।

अनुच्छेद-दो

प्रत्यर्पण अपराध

(1) इस संधि के उद्देश्यों के लिए कोई प्रत्यर्पण अपराध वह आचरण माना जाएगा जिसके लिए प्रत्येक संधिदाकारी राज्य के कानूनों के अंतर्गत कम से कम एक वर्ष की अवधि का दण्ड दिया जा सकता है।

(2) कोई अपराध प्रत्यर्पणीय अपराध हो सकता है, इस बात के बावजूद कि वह कराधान अथवा राजस्व से संबंधित है अथवा शुद्ध रूप से राजकोषीय स्वरूप का है।

अनुच्छेद-तीन

संपत्ति अपराध

किसी प्रत्यर्पण अपराध के लिए इस संधि के अनुसरण में इस बात के बावजूद प्रत्यर्पण उपलब्ध होगा कि वांछित व्यक्ति द्वारा अपराध पूर्णतः अथवा अंशतः अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य में किया गया, यदि उस राज्य के कानून के अंतर्गत वह आचरण अथवा इसका प्रभाव, अथवा संपूर्ण रूप में इसके इच्छित प्रभावों को अनुरोधकर्ता राज्य के भूक्षेत्र में प्रत्यर्पणीय अपराध माना जाता है।

अनुच्छेद-चार

राष्ट्रिकों का प्रत्यर्पण

इस संधि में क्षेत्रीय अपराध के संबंध में अथवा किसी अतिरिक्त देशीय अपराध के संबंध में अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य द्वारा अपने राष्ट्रिकों का प्रत्यर्पण करने में कोई बाधा नहीं होगी।

अनुच्छेद-पांच

राजनैतिक अपराध अपवाद

(1) प्रत्यर्पण से इनकार किया जा सकता है यदि जिस अपराध के लिए अनुरोध किया गया है वह राजनैतिक स्वरूप का अपराध है।

(2) इस संधि के उद्देश्य के लिए निम्नलिखित अपराधों को राजनैतिक स्वरूप का अपराध नहीं माना जाएगा—

(क) विमानों की गैर-कानूनी जब्ती के दमन से संबद्ध अभिसमय, जिसे हेग में 16 दिसम्बर, 1970 को हस्ताक्षर के लिए रखा गया, के क्षेत्र में आने वाले अपराध;

(ख) नागर विमानन सुरक्षा के विरुद्ध गैर-कानूनी कृत्यों के दमन से संबद्ध अभिसमय, जिसे मॉन्ट्रियल में 23 सितम्बर 1971 को हस्ताक्षर के लिए रखा गया, के क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले अपराध;

(ग) राजनयिक एजेंटों सहित अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संरक्षित व्यक्तियों के विरुद्ध अपराधों की रोकथाम और दमन से संबद्ध अभिसमय, जिसे 14 सितम्बर, 1973 को न्यूयार्क में हस्ताक्षर के लिए रखा गया, के क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला कोई अपराध;

(घ) बंधक बनाने के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय, जिसे 18 दिसम्बर, 1977 को न्यूयार्क में हस्ताक्षर के लिए रखा गया के क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला कोई अपराध;

(ङ) हत्या;

(च) मानव हत्या अथवा गैर-इरादतन हत्या;

(छ) हमला जिससे शारीरिक छति पहुंचे अथवा चाहे वह शारीरिक चोट किसी हथियार, किसी खतरनाक पदार्थ

अथवा अन्य के द्वारा शारीरिक चोट पहुंचाने के लिए की गयी हो;

(ज) विस्फोट करना जिससे जीवन को खतरा पहुंचने अथवा संपत्ति को गंभीर हानि पहुंचने की संभावना हो;

(झ) किसी व्यक्ति द्वारा विस्फोटक पदार्थ का निर्माण अथवा उन्हें पास में रखना जिसके द्वारा वह स्वयं या अन्य व्यक्ति के जरिए जीवन को खतरा पहुंचाने अथवा संपत्ति को गंभीर क्षति पहुंचाने की मंशा रखता है;

(ञ) किसी व्यक्ति द्वारा आग्नेयास्त्र अथवा गोला-बारूद रखना जो स्वयं अथवा किसी व्यक्ति के जरिए अन्य व्यक्तियों के जीवन को खतरे में डालने की मंशा रखता है;

(ट) किसी व्यक्ति द्वारा स्वयं की अथवा अन्य व्यक्ति की गिरफ्तारी अथवा कैद का प्रतिरोध करने अथवा रोकने की मंशा से आग्नेयास्त्रों का प्रयोग;

(ठ) जीवन को खतरे में डालने की मंशा से सार्वजनिक उपयोग के अथवा अन्य उद्देश्यों के लिए उपयोग में लायी जाने वाली संपत्तियों को क्षति पहुंचाना और इस बात पर ध्यान नहीं देना कि इससे अन्य के जीवन को खतरा पहुंच सकता है;

(ड) बंधक बनाने सहित अपहरण, अपगमन, झूठी कैद अथवा गैर-कानूनी गिरफ्तारी;

(ढ) हत्या के लिए उकसाना;

(ण) आत्मत्याग से संबंधित कोई अन्य अपराध जिसे अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य के कानून के अंतर्गत अनुरोध किये जाने के समय राजनैतिक स्वरूप का अपराध नहीं माना जाए;

(त) पूर्ण में किए गए किन्हीं अपराधों में प्रवास अथवा षड्यंत्र अथवा ऐसा कोई अपराध करने वाले अथवा प्रवास करने वाले के साथ सह-अपराधी के रूप में भाग लेना।

अनुच्छेद-छह

प्रत्यर्पण और अभिवोजन

(1) अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य किसी व्यक्ति के प्रत्यर्पण अनुरोध को अस्वीकार कर सकता है यदि उस व्यक्ति जिसके लिए प्रत्यर्पण अनुरोध किया गया है, पर उस राज्य प्रत्यर्पण अपराध के लिए मुकदमा चलाया जा रहा है।

(2) यदि अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य इस अनुच्छेद के पैरा 1 में उल्लिखित कारण के आधार पर प्रत्यर्पण के अनुरोध को अस्वीकार करता है तो वह मुकदमा चलाए जाने पर विचार करने के लिए इस मामले को अपने सक्षम प्राधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत करेगा। वे सक्षम प्राधिकारी उस राज्य के कानून के अधीन गंभीर प्रकृति के किसी अपराध के मामले के समान ही अपना निर्णय करेंगे।

(3) यदि सक्षम प्राधिकारी ऐसे मामले में मुकदमा नहीं चलाने का निर्णय लेते हैं तो इस संधि के अनुसार प्रत्यर्पण के अनुरोध पर पुनर्विचार किया जाएगा।

अनुच्छेद-सात

प्रत्यर्पण से इनकार करने के आधार

(1) किसी व्यक्ति को प्रत्यर्पित नहीं किया जा सकता यदि :

(क) वह अनुरोध प्राप्तकर्ता पक्ष को सहमत कर लेता है कि सभी परिस्थितियों को देखते हुए उसे प्रत्यर्पित करना निम्न कारणों से अन्यायपूर्ण अथवा अनौचित्यपूर्ण होगा :

(i) तुच्छ किस्म के अपराध जिसके लिए उसे आरोपित अथवा दोषसिद्ध किया गया हो;

अथवा

(ii) जिस समय तथाकथित रूप से उस पर अपराध का आरोप लगाया गया हो अथवा गैर कानूनी रूप से फंसा हो जैसी भी स्थिति हो; अथवा

(iii) उसके विरुद्ध दोषारोपण न्याय के हित में नहीं किया गया है; अथवा

(ख) अपराध जिसके लिए वह अभियुक्त है अथवा दोषसिद्ध है, एक सैन्य अपराध है जो सामान्य आपराधिक कानून के अधीन भी अपराध नहीं है।

(2) किसी व्यक्ति जिसे एक प्रत्यर्पण अपराध के लिए दोषसिद्ध पाया गया हो, को तब तक प्रत्यर्पित नहीं किया जाएगा जब तक कि उसे कैद अथवा चार माह अथवा उससे अधिक की अवधि की अन्य प्रकार की हिरासत की सजा न दी गई हो।

(3) किसी व्यक्ति को प्रत्यर्पित नहीं किया जाएगा, यदि उसने अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य के क्षेत्र में अपराध, जिसके लिए उसका प्रत्यर्पण अनुरोध किया गया है, के विरुद्ध अपील की है, उसे अनुरोध प्राप्तकर्ता राज्य के किसी कानून के अधीन उसकी पिछली विमुक्ति अथवा दोषसिद्धि के आधार पर विमुक्त कर दिया जाएगा।

अनुच्छेद-आठ

समर्पण का आस्थगन

(1) यदि वांछित व्यक्ति के विरुद्ध अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य के क्षेत्र में आपराधिक कार्रवाईयाँ चल रही हों अथवा उसे आपराधिक कार्रवाईयों के अधीन कानूनी रूप से हिरासत में लिया गया हो तो आपराधिक कार्रवाईयाँ पूरी होने अथवा उसकी हिरासत अवधि समाप्त होने तक उसके प्रत्यर्पण को आस्थगित किया जा सकता है।

(2) किसी वांछित व्यक्ति को प्रत्यर्पित नहीं किया जा सकता यदि;

(क) इसका निर्णय अनुरोध प्राप्तकर्ता राज्य के कानून के प्रावधानों के अनुसार किया गया हो कि इसका प्रत्यर्पण किया जा सकता है।

(ख) उस राज्य के कानून द्वारा किसी अपेक्षित अवधि के बीत जाने के बाद।

अनुच्छेद-नौ

प्रत्यर्पण प्रक्रियाएं

(1) इस संधि के अधीन प्रत्यर्पण का अनुरोध राजनयिक माध्यम से किया जाएगा।

(2) अनुरोध के साथ निम्नलिखित संलग्न होंगे;

(क) जहां तक संभव हो वांछित व्यक्ति के सही विवरण के साथ-साथ उसकी पहचान, राष्ट्रीयता और निवास स्थान का पता लगाने में सहायक अन्य जानकारी;

(ख) जिस अपराध के लिए प्रत्यर्पण अनुरोध किया गया है उसके तथ्यों का विवरण, और

(ग) तदनुकूल कानून का पाठ, यदि कोई हो;

(i) उस अपराध की व्याख्या; और

(ii) उस अपराध के लिए निर्धारित अधिकतम सजा।

(3) यदि अनुरोध किसी आरोपी व्यक्ति के लिए है तो इसके साथ अनुरोधकर्ता राज्य के न्यायाधीश, मैजिस्ट्रेट अथवा सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी गिरफ्तारी वारंट भी संलग्न किया जाएगा और ऐसे साक्ष्य के साथ-साथ वह साक्ष्य भी कि जिस व्यक्ति के लिए अनुरोध किया गया है वही व्यक्ति है जिसके लिए गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है, को औचित्यपूर्ण उहसता है, भी शामिल किए जाएंगे।

(4) यदि अनुरोध किसी ऐसे व्यक्ति, जिसकी पहले ही दोषसिद्धि हो चुकी है और सजा हो चुकी है, से संबंधित है तो इसके साथ निम्नलिखित भी संलग्न होंगे :-

(क) दोषसिद्धि और सजा का प्रमाण पत्र

(ख) एक वक्तव्य कि वह व्यक्ति दोषसिद्धि अथवा सजा पर कोई प्रश्न करने का अधिकारी नहीं है और वह बताया जाएगा कि कितनी और सजा रह गई है।

(5) यदि अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य यह मानता है कि इस संधि के प्रयोजन के लिए प्रस्तुत साक्ष्य अथवा जानकारी अनुरोध पर निर्णय लेने के लिए नाकافی है तो अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य द्वारा दी गई समस्यावधि के भीतर अतिरिक्त साक्ष्य अथवा जानकारी प्रस्तुत की जाएगी।

अनुच्छेद-दस

अन्तिम गिरफ्तारी

(1) तात्कालिक मामलों में वांछित व्यक्ति को, अनुरोधकर्ता राज्य के सक्षम प्राधिकारी के अनुरोध पर, अनुरोध प्राप्तकर्ता राज्य के कानून के अनुसार अन्तिम रूप से गिरफ्तार किया जा सकता है। अनुरोध में उस व्यक्ति के प्रत्यर्पण के अनुरोध की मंशा और गिरफ्तारी के वारंट के होने का कथन अथवा उसके विरुद्ध दोषसिद्धि का संकेत होना चाहिए और यदि उपलब्ध हो तो उसका हुलिया और

ऐसी अन्य जानकारी, यदि कोई है, जो अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य के क्षेत्र में, किए गए अपराध के लिए अथवा वांछित व्यक्ति के दोषसिद्ध हो जाने के लिए आवश्यक होगी, संलग्न होगी।

(2) ऐसे अनुरोध प्राप्त होने पर गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी की तारीख से 60 दिन की समाप्ति पर रिहा कर दिया जाएगा। यदि उसका प्रत्यर्पण अनुरोध प्राप्त नहीं होता है यदि प्रत्यर्पण अनुरोध बाद में प्राप्त होता है तो यह प्रावधान वांछित व्यक्ति के प्रत्यर्पण की आगे की कार्यवाही को नहीं रोकेगा।

अनुच्छेद-ग्यारह

विशिष्टता का नियम

(1) किसी भी व्यक्ति पर जो इस अनुच्छेद के पैराग्राफ (2) में निर्धारित अवधि के दौरान इस संधि के तहत अनुरोधकर्ता राज्य के क्षेत्र में लौटाया जाता है, अनुरोधकर्ता राज्य क्षेत्र में लौटाए जाने के पूर्व निम्नलिखित को छोड़ते हुए किए गए किसी भी अपराध के लिए अथवा उसके संबंध में अनुरोधकर्ता राज्य के क्षेत्र में कार्रवाई नहीं की जाएगी :

- (क) वह अपराध जिसके संबंध में उस लौटाया गया हो;
- (ख) उसकी वापसी हासिल करने के प्रयोजन से सिद्ध तथ्यों द्वारा उजागर कोई छोटा अपराध जिसमें वह अपराध शामिल नहीं है जिसके लिए कानूनन वापसी का आदेश नहीं जारी किया गया हो अथवा किया जाना हो; अथवा
- (ग) कोई भी ऐसा अपराध जिसके लिए अनुरोधप्राप्तकर्ता पक्षकार उस पर कार्रवाई की अनुमति प्रदान करे जिसमें वह अपराध शामिल नहीं है, जिसके लिए कानूनन वापसी का आदेश नहीं जारी किया गया हो अथवा किया जाना हो।

(2) इस अनुच्छेद के पैराग्राफ (1) में संदर्भित अवधि वह अवधि है जो उसके अनुरोधकर्ता राज्य के क्षेत्र में दाखिल होने अथवा इस संधि के तहत उसकी वापसी के दिन से आरम्भ होकर उस दिन के 45 दिनों बाद समाप्त हो जाएगी जिस दिन पर उसे अनुरोधकर्ता राज्य को छोड़ने का अवसर हासिल होगा।

(3) इस अनुच्छेद के पैराग्राफ (1) के उपबंध उन अपराधों पर लागू नहीं होंगे जो इस संधि के तहत किसी व्यक्ति द्वारा वापसी के बाद अंजाम दिया गया हो तथा इस प्रकार के अपराधों के संबंध में उत्पन्न मामलों पर भी लागू नहीं होंगे।

(4) कोई भी व्यक्ति किसी तीसरे राज्य को पुनः प्रत्यर्पित नहीं किया जाएगा जब तक कि सौंपे गए राज्य के क्षेत्र को छोड़ने का अवसर प्राप्त होने पर भी उसने अपनी अंतिम रिहाई के सात दिनों के भीतर उस क्षेत्र को नहीं छोड़ा अथवा उस क्षेत्र को छोड़ने के बाद वापस उसी क्षेत्र में आ गया हो।

अनुच्छेद-बारह

साक्ष्य

(1) अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य के प्राधिकारी प्रत्यर्पण हेतु किसी भी कार्रवाई में प्रमाणीकृत होने पर अधिभोजन के तथ्य का ब्यौरा देने वाले न्यायिक दस्तावेज अथवा कोई वारन्ट अथवा कोई प्रमाणपत्र, शपथ पर अथवा पुष्टि द्वारा लिया गया कोई प्रमाण साक्ष्य के तौर पर प्रस्तुत करेंगे :

- (क)(i) अनुरोधकर्ता राज्य के जज, मजिस्ट्रेट अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित होने वाले वारन्ट अथवा मूल दस्तावेज प्रमाणित किए जाने वाले मामले में; और
- (ii) कुछ गवाहों की शपथ द्वारा अथवा अनुरोधकर्ता राज्य के उपयुक्त मंत्री की आधिकारिक मुहर के साथ सील करने के माध्यम से; अथवा
- (ख) इस प्रकार जैसाकि अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य के कानून द्वारा अनुमत्त हो।

(2) पैराग्राफ (1) में उल्लिखित साक्ष्य अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य में प्रत्यर्पण कार्रवाई में स्वीकार्य होगा चाहे उसकी शपथ अथवा पुष्टि अनुरोधकर्ता राज्य में अथवा किसी तीसरे राज्य में की गई हो।

अनुच्छेद-तेरह

प्रतिस्पर्धी अनुरोध

यदि उसी व्यक्ति का प्रत्यर्पण उसी अथवा भिन्न अपराधों के लिए संविदाकारी राज्य अथवा उस तीसरे राज्य द्वारा अपेक्षित हो, जिसके साथ अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य ने प्रत्यर्पण व्यवस्था की हो तो अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य यह निर्धारण करेगा कि उस व्यक्ति को किस राज्य में प्रत्यर्पित किया जाए और वह संविदाकारी राज्य को अधिमानता देने के लिए बाध्य नहीं होगा।

अनुच्छेद-चौदह

मृत्यु दण्ड

यदि अनुरोधकर्ता राज्य के कानून के अंतर्गत अपेक्षित व्यक्ति को उस अपराध के लिए मृत्यु दण्ड दिया जा सकता है, जिसके लिए प्रत्यर्पण का अनुरोध किया गया हो किन्तु अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य के कानून के तहत समान मामले में मृत्युदण्ड का प्रावधान नहीं हो तो प्रत्यर्पण से इंकार किया जा सकता है जब तक कि अनुरोधकर्ता राज्य ऐसा आश्वासन नहीं देता, जिसे अनुरोधकर्ता इस बात के लिए पर्याप्त समझे कि मृत्यु दण्ड नहीं दिया जाएगा।

अनुच्छेद-पंद्रह

सुपुर्दगी

(1) यदि प्रत्यर्पण प्रदान किया जाए तो अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य के प्राधिकारियों द्वारा अपेक्षित व्यक्ति को उस राज्य के क्षेत्र से प्रस्थान के ऐसे सुविधाजनक स्थान से भेजा जाएगा जहाँ से अनुरोधकर्ता राज्य ईंगित करे।

(2) अनुरोधकर्ता राज्य अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य के क्षेत्र से अपेक्षित व्यक्ति को एक महीने के भीतर अथवा अनुरोध प्राप्तकर्ता राज्य के कानून के तहत यथा-अनुमत्य अवधि के भीतर हटा लेगा। यदि वह इस अवधि के भीतर उसे नहीं हटाता तो अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य उसे उसी अपराध के लिए प्रत्यर्पित करने से इंकार कर सकता है।

अनुच्छेद-सहस्र

संपत्ति अन्वेषण

(1) जब प्रत्यर्पण का अनुरोध स्वीकार हो जाता है तो अनुरोध-प्राप्तकर्ता राज्य अनुरोध प्राप्त होने पर और अपने कानूनों में अनुमत्य होने पर ऐसी वस्तुएं (जिनमें धन भी शामिल है) जो कि अपराध के प्रमाण अथवा सबूत का काम करेगा, अनुरोधकर्ता राज्य को सौंप देगा।

(2) यदि विवादस्पद वस्तुएं अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य के राज्यक्षेत्र में जल अथवा अधिगृहीत की जाने वाली हों तो अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य, सम्बन्धित कार्यवाहियों के संबंध में, इन्हें अस्थायी रूप से अपने पास रोकें रख सकता है या फिर इस शर्त पर अनुरोधकर्ता राज्य को सौंप सकता है कि (अवश्यक होने पर) इन्हें लौटा दिया जाएगा।

(3) इन उपबंधों से अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य के अथवा वांछित व्यक्ति को छोड़कर किसी अन्य व्यक्ति के अधिकारों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। जहां किसी के ऐसे स्वत्ताधिकार मौजूद हों जहां ये वस्तुएं, कार्यवाहियां पूरी हो जाने के बाद यथाशीघ्र बिना किसी प्रभार के अनुरोधकर्ता राज्य को वापस कर दी जाएंगी।

अनुच्छेद-सत्रह

प्रत्यर्पण में परस्पर कानूनी सहायता

प्रत्येक सविदाकारी पक्षकार, अपने कानून में अनुमत्य सीमा तक, उस अपराध संबंधी दण्डिक मामलों में जिसके लिए कि प्रत्यर्पण का अनुरोध किया गया है, दूसरे पक्षकार के लिए व्यापक पास्परिक सहायता की व्यवस्था करेगा।

अनुच्छेद-अठारह

दस्तावेज एवं खर्च

(1) यदि किसी मामले विशेष में अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य चाहे तो अनुरोधकर्ता राज्य, इस संधि के उपबंधों के अनुरूप प्रस्तुत किए गए किसी दस्तावेज का अनुवाद भिजवाने की व्यवस्था करेगा।

(2) प्रत्यर्पण के अनुरोध की वजह से अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य के राज्य क्षेत्र में किया गया व्यय, उसी राज्य द्वारा वहन किया जाएगा।

(3) इस अनुरोध से उद्भूत किन्हीं कार्यवाहियों में अनुरोधकर्ता राज्य के प्रतिनिधित्व के संबंध में अपेक्षित सभी व्यवस्थाएं अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य द्वारा की जाएंगी।

अनुच्छेद-उन्नीस

अन्तर्राष्ट्रीय अभिसमयों/संधियों के अधीन दायित्व

इस संधि के कारण, सविदाकारी राज्यों के उन अधिकारों एवं दायित्वों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा जो उन्हें अंतर्राष्ट्रीय अभिसमयों/संधियों के पक्षकार होने के कारण प्राप्त हैं।

अनुच्छेद-बीस

अंतिम प्रावधान

(1) यह संधि उन अनुरोधों पर लागू होगी जो इस संधि के प्रवृत्त होने के बाद किए जाएंगे चाहे फिर संगत कृत्य अथवा चूक उस तिथि से पहले ही घटित क्यों न हुए हों।

(2) इस संधि की अभिपुष्टि की जानी होगी और अभिपुष्टि के दस्तावेजों का यथाशीघ्र आदान-प्रदान किया जाएगा। यह संधि, अभिपुष्टि के दस्तावेजों के आदान-प्रदान की तिथि से ही प्रवृत्त होगी।

(3) दोनों में से कोई भी सविदाकारी राज्य, इस संधि को किसी भी समय, दूसरे पक्ष को राजनयिक माध्यम से नोटिस देकर समाप्त कर सकता है; और यदि ऐसा नोटिस दे दिया जाता है तो यह संधि नोटिस की प्राप्ति के छः महीने परचात अप्रभावी हो जाएगी।

इसके साक्ष्य में अधोहस्ताक्षरकर्ताओं ने अपनी-अपनी सरकारों से इस संबंध में प्राधिकृत होकर इस संधि पर हस्ताक्षर किए हैं।

आज नई दिल्ली में इसी सन् दो हजार तीन के नवम्बर माह के 21वें दिन हिन्दी और अंग्रेजी की दो दो प्रतियों में हस्ताक्षरित। दोनों ही भाषाओं के पाठ समान रूप से प्रामाणिक हैं। निर्वचन में विसंगति की स्थिति में अंग्रेजी पाठ सर्वोपरि होगा।

इसलिए अब प्रत्यर्पण अधिनियम, 1962 (1962 का 34) की धारा 3, उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्वारा यह निदेश देती है कि अध्याय III के अलावा उक्त अधिनियम के प्रावधान इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से मॉरीशस गणराज्य के लिए लागू होंगे।

[सं. टी 413/03/2003]

पी. एम. मीणा, संयुक्त सचिव (कॉन्सुलर)

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS NOTIFICATION

New Delhi, the 19th September, 2008

TREATY ON EXTRADITION BETWEEN THE REPUBLIC OF INDIA AND

THE REPUBLIC OF MAURITIUS

G.S.R. 661(E).—Whereas the Extradition Treaty between the Republic of India and the Republic of Mauritius was signed at New Delhi on 21st November, 2003; and the exchange of the Instrument of Ratification of the Treaty took place at Port Louis on 23rd June, 2008 and has entered into force from the date of the exchange of instruments of ratification in terms of Article 20, and which Treaty provides as follows:

The Government of the Republic of India and the Government of the Republic of Mauritius;

Desirous of making more effective the corporation of the two countries in the suppression of crime by making further provision for the reciprocal extradition offenders;

Recognising that concrete steps are necessary to combat terrorism;

Have agreed as follows:

Article 1—Duty to Extradite

(1) Each Contracting State undertakes to extradite to the other, in the circumstances and subject to the conditions specified in this Treaty, any person who, being accused or convicted of an extradition offence as described in Article 2, committed within the territory of the one State, is found within the territory of the other State, whether such offence was committed before or after the entry into force of this Treaty.

(2) Extradition shall also be available in respect of an extradition offence as described in Article 2 committed outside the territory of the Requesting State but in respect of which it has jurisdiction if the Requested State would, in corresponding circumstances, have jurisdiction over such as offence. In such circumstances the Requested State shall have regard to all the circumstances of the case including the seriousness of the offence.

(3) In addition, extradition shall be available for an extradition offence as described in Article 2 :

- (a) if it is committed in a third State by a national of the Requesting State and the Requesting State bases its jurisdiction on the nationality of the offender; and
- (b) if it occurred in the Requesting State, it would be an offence under the law of that State punishable with imprisonment for a term of at least one year.

Article 2—Extradition Offences

(1) An extradition offence for the purposes of this Treaty is constituted by conduct which under the laws of each Contracting State is punishable by a term of imprisonment for a period of at least one year.

(2) An offence may be an extradition offence notwithstanding that it relates to taxation or revenue or is one of a purely fiscal character.

Article 3—Composite Offences

Extradition shall be available in accordance with this Treaty for an extradition offence, notwithstanding that the conduct of the person sought occurred wholly or in part in the Requested State, if under the law of that State this conduct and its effects, or its intended effects, taken as a whole, would be regarded as constituting the commission of an extradition offence in the territory of the Requesting State.

Article 4—Extradition of Nationals

Nothing in this Treaty shall preclude the extradition by the Requested State of its nationals either in respect of a territorial offence or in respect of an extraterritorial offence.

Article 5—The Political Offence Exception

(1) Extradition may be refused if the offence of which it is requested is an offence of a political character.

(2) For the purpose of this Treaty the following offences shall not be regarded as offences of a political character :

- (a) an offence within the scope of the Convention for the Suppression of Unlawful Seizure of Aircraft, opened for signature at the Hague on 16 December, 1970;
- (b) an offence within the scope of the Convention for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Civil Aviation, opened for signature at Montreal on 23 September, 1971;
- (c) an offence within the scope of the Convention on the Prevention and Punishment of Crimes against internationally Protected Persons, including Diplomatic Agents, opened for signature at New York on 14 December, 1973;
- (d) an offence within the scope of the International Convention against the Taking of Hostages, opened for signature at New York on 18 December, 1979;
- (e) murder;
- (f) manslaughter or culpable homicide;
- (g) assault occasioning actual bodily harm, or causing injury, maliciously wounding or inflicting grievous bodily harm whether by means of a weapon, a dangerous substance or otherwise;
- (h) the causing of an explosion likely to endanger life or cause serious damage to property;
- (i) the making or possession of an explosive substance by a person who intends either himself or through another person to endanger life or cause serious damage to property;
- (j) the possession of a firearm or ammunition by a person who intends either himself or through another persons to endanger life;
- (k) the use of a firearm by a person with intent to resist or prevent the arrest or detention of himself or another person;
- (l) damaging property whether used for public utilities or otherwise with intent to endanger life or with reckless disregard as to whether the life of another would thereby be endangered;
- (m) kidnapping, abduction, false imprisonment or unlawful detention, including the taking of a hostage;
- (n) incitement to murder;
- (o) any other offence related to terrorism which at the time of the request is, under the law of the

Requested State, not to be regarded as an offence of a political character;

- (p) an attempt or conspiracy to commit any of the foregoing offences or participation as an accomplice of a person who commits or attempts to commit such an offence.

Article 6—Extradition and Prosecution

(1) The request for extradition may be refused by the Requested State if the person whose extradition is sought may be tried for the extradition offence in the courts of that State.

(2) Where the Requested State refuses a request for extradition for the reason set out in paragraph 1 of this Article, it shall submit the case to its competent authorities so that prosecution may be considered. Those authorities shall take their decision in the same manner as in the case of any offence of a serious nature under the law of that State.

(3) If the competent authorities decide not to prosecute in such a case, the request for extradition shall be reconsidered in accordance with this Treaty.

Article 7—Grounds for Refusal of Extradition

(1) A person may not be extradited if:

- (a) he satisfies the Requested State that it would, having regard to all the circumstances, be unjust or oppressive to extradite him by reason of:

(i) the trivial nature of the offence of which he is accused or was convicted; or

(ii) the passage of time since he is alleged to have committed it or to have become unlawfully at large, as the case may be; or

(iii) the accusation against him not having been made in good faith in the interests of justice; or

(b) the offence of which he is accused or convicted is a military offence which is not also an offence under the general criminal law.

(2) A person who has been convicted of an extradition offence may not be extradited therefor unless he was sentenced to imprisonment or other form of detention for a period of four months or more.

(3) A person may not be extradited if he would, if proceeded against in the territory of the Requested State for the offence for which his extradition is requested, be entitled to be discharged under any rule of law of the Requested State relating to previous acquittal or conviction.

Article 8—Postponement of Surrender

(1) If criminal proceedings against the person sought are instituted in the territory of the Requested State, or he

is lawfully detained in consequence of criminal proceedings, the decision whether or not to extradite him may be postponed until the criminal proceedings have been completed or he is no longer detained.

(2) A person sought may not be extradited until:

(a) it has been decided in accordance with the law of the Requested State that he is liable to be extradited; and

(b) the expiration of any further period which may be required by the law of that State.

Article 9—Extradition Procedures

(1) The request for extradition under this Treaty shall be made through the diplomatic channel.

(2) The request shall be accompanied by:

(a) as accurate a description as possible of the person sought, together with any other information which would help to establish his identity, nationality and residence;

(b) a statement of the facts of the offence for which extradition is requested, and

(c) the text, if any, of the law:

(i) defining that offence; and

(ii) prescribing the maximum punishment for that offence.

(3) If the request relates to an accused person, it must also be accompanied by a warrant of arrest issued by a judge, magistrate or other competent authority in the territory of the Requesting State and by such evidence as, according to the law of the Requested State, would justify his committal for trial if the offence had been committed in the territory of the Requested State, including evidence that the person requested is the person to whom the warrant of arrest refers.

(4) If the request relates to a person already convicted and sentenced, it shall also be accompanied:

(a) by a certificate of the conviction and sentence;

(b) by a statement that the person is not entitled to question the conviction or sentence and showing how much of the sentence has not been carried out.

(5) If the Requested State considers that the evidence produced or information supplied for the purposes of this Treaty is not sufficient in order to enable a decision to be taken as to the request, additional evidence or information shall be submitted within such time as the Requested State shall require.

Article 10—Provisional Arrest

(1) In urgent cases the person sought may, in accordance with the law of the Requested State, be provisionally arrested on the application of the competent authorities of the Requesting State. The application shall contain an indication of intention to request the extradition

of that person and statement of the existence of a warrant of arrest or a conviction against him, and, if available, his description and such further information, if any, as would be necessary to justify the issue of a warrant of arrest had the offence been committed, or the person sought been convicted, in the territory of the Requested State.

(2) A person arrested upon such an application shall be set at liberty upon the expiration of 60 days from the date of his arrest if request for his extradition shall not have been received. This provision shall not prevent the institution of further proceedings for the extradition of the person sought if a request is subsequently received.

Article 11—Rule of Speciality

(1) Any person who is returned to the territory of the Requesting State under this Treaty shall not, during the period described in paragraph (2) of this Article, be dealt with in the territory of the Requesting State for or in respect of any offence committed before he was returned to that territory other than :

- (a) the offence in respect of which he was returned;
- (b) any lesser offence disclosed by the facts proved for the purposes of securing his return other than an offence in relation to which an order for his return could not lawfully be made; or
- (c) any other offence in respect of which the Requested Party may consent to his being dealt with other than an offence in relation to which an order for his return could not lawfully be made or would not in fact be made.

(2) The period referred to in paragraph (1) of this Article is the period beginning with the day of his arrival in the territory of the Requesting State or his return under this Treaty and ending forty-five days after the first subsequent day on which he has the opportunity to leave the territory of the Requesting State.

(3) The provisions of paragraph (1) of this Article shall not apply to offences committed after the return of a person under this Treaty or matters arising in relation to such offences.

(4) A person shall not be re-extradited to a third State, except when, having had an opportunity to leave the territory of the State to which he has been surrendered, he has not done so within sixty days of his final discharge, or has returned to that territory after having left it.

Article 12—Evidence

(1) The authorities of the Requested State shall admit as evidence, in any proceedings for extradition, any evidence taken on oath or by way of affirmation, any warrant and any certificate of, or judicial document stating the fact of, a conviction, if it is authenticated :

- (a)(i) in the case of a warrant being signed, or in the case of any original document by being

certified, by a judge, magistrate or other competent authority of the Requesting State; and

- (ii) either by oath of some witness or by being sealed with the official seal of the appropriate Minister of the Requesting State; or
- (b) In such other manner as may be permitted by the law of the Requested State.

(2) The evidence described in paragraph (1) shall be admissible in extradition proceedings in the Requested State whether sworn or affirmed in the Requesting State or in some third State.

Article 13—Competing Requests

If extradition of the same person whether for the same offence or for different offences is requested by a Contracting State and a third State with which the Requested State has an extradition arrangement, the Requested State shall determine to which State the person shall be extradited, and shall not be obliged to give preference to the Contracting State.

Article 14—Capital Punishment

(1) If under the law of the Requesting State the person sought is liable to the death penalty for the offence for which his extradition is requested, but the law of the Requested State does not provide for the death penalty in a similar case, extradition may be refused unless the Requesting State gives such assurance as the Requested State considers sufficient that the death penalty will not be carried out.

Article 15—Surrender

(1) If extradition is granted, the person sought shall be sent by the authorities of the Requested State to such convenient point of departure from the territory of that State as the Requesting State shall indicate.

(2) The Requesting State shall remove the person sought from the territory of the Requested State within one month or such longer period as may be permitted under the law of the Requested State. If he is not removed within that period, the Requested State may refuse to extradite him for the same offence.

Article 16—Surrender of Property

(1) When a request for extradition is granted, the Requested State shall, upon request and so far as its laws allow, hand over to the Requesting State articles (including sums of money) which may serve as proof or evidence of the offence.

(2) If the articles in question are liable to seizure or confiscation in the territory of the Requested State, the latter may, in connection with pending proceedings, temporarily retain them or hand them over on condition that they are returned.

(3) These provisions shall not prejudice the rights of the Requested State or any person other than the person

sought. When these rights exist the articles shall on request be returned to the Requested State without charge as soon as possible after the end of the proceedings.

Article 17—Mutual Legal Assistance in Extradition

Each Contracting State shall, to the extent permitted by its law afford the other the widest measure of mutual assistance in criminal matters in connection with the offence for which extradition has been requested.

Article 18—Documents and Expenses

(1) If in any particular case the Requested State so requires, the Requesting State shall supply a translation of any document submitted in accordance with the provisions of this treaty.

(2) Expenses incurred in the territory of the Requested State by reason of the request for extradition shall be borne by that State.

(3) The Requested State shall make all the arrangements which shall be requisite with respect to the representation of the Requesting State in any proceedings arising out of the request.

Article 19—Obligations under International Conventions/Treaties

The present Treaty shall not affect the rights and obligations of the Contracting States arising from International Conventions/Treaties to which they are parties.

Article 20—Final provisions

(1) The present Treaty shall apply to requests made after its entry into force, even if the relevant acts or omissions occurred prior to that date.

(2) This Treaty shall be subject to ratification and the instruments of ratification shall be exchanged as soon as possible. It shall enter into force on the date of the exchange of instruments of ratification.

(3) Either of the Contracting States may terminate this Treaty at any time by giving notice to the other through the diplomatic channel; and if such notice is given the Treaty shall cease to have effect six months after the receipt of the notice.

In witness whereof, the Undersigned being duly authorized thereto by their respective Governments, have signed this Treaty.

Done in duplicate at New Delhi on this the 21st day of November, 2003, in Hindi and English, both languages being equally authentic. In case of any divergence of interpretation, the English text shall prevail.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Extradition Act, 1962 (34 of 1962), the Central Government hereby directs that the provisions of the said Act, other than Chapter III, shall apply to the Republic of Mauritius from the dated of the publication of this notification.

[No. T 413/03/2003]

P. M. MEENA, Jt. Secy. (Consular)

3604 GI/08-3